registered during the period 1.12.91 to 30.11.92 against builders.

(c) Penal action against builders against whom prosecution results in conviction has to be taken by the competent courts in accordance with the law.

(d) and (e) A rating agency is proposed to be set up to give approved status to developers and property agents on the basis of clearly defined criteria based on the qualifications and previous performance of the builders and property agents. A model legislation for the registration and regulation of builders has been referred for necessary action to state governments.

Land-Racketeers and Speculators in Developed Colonies of Delhi

3969. SHRI JAGMOHAN: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of houses in the well-planned and recently developed colonies in Delhi like Greater Kailash-II Panchsheel, Vasant Vihar, Anand Lok and Sarvapriya Vihar have been purchased or contracted by the landracketeers and speculators with the sole objective of demolishing them and putting up new constructions in violations of the municipal bye-laws, zoning and density regulations;

(b) whether it is also a fact that instead of one or two dwelling units that existed previously, six to eight dwelling units have now been put up or are being put up; and

(c) if answers to (a) and (b) above be in the affirmative what corrective steps are being taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Municipal Corporation of Delhi has reported that no such instance has come to their notice. Action is taken by local bodies in respect of all constructions violating the building regulations and master plan which come to their notice.

(b) and (c) Question does not arise.

3970. *[Transferred to the 17th December, 1992]*

कमजोर वर्गों के लिए आवास सुविधाएं

3971. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को आवास सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस संबंध में शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने प्रतिशत प्रगति की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) राष्ट्रीय आवास नीति में लोगों की आवास स्थितियों को सुधारने, विशेषकर बेघरों, अपर्याप्त मकानों में बसे लोगों और उपेक्षित वर्गों को विकसित भूमि, भवन निर्माण सामग्रियों, वित्त तथा प्रौद्योगिकी की पहुंच के माध्यम से स्वयं के लिए सस्ते मकान प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इस संबंध में योजनायें और कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा तैयार और कार्यान्वित की जानी हैं। केन्द्रीय सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आवास सहायता की केन्द्रीय योजनाओं, शहरी निर्धनों की आश्रय सुधार और पटरी निवासियों के लिए रैन बसेरा योजनाओं को चलाती है। हुडको शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग की आवास योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था कर रहा है जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक छोटे रिहायशी एककों के लिए दिए ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करता है।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय होने के नाते समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित विभिन्न सामाजिक आवास योजनायें राज्य सरकारों द्वारा राज्य योजना प्रावधानों में से तैयार और कार्यान्वित की जाती है। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संबंध में लक्ष्य भी तय किए हैं। तथापि, नितान्त रूप